

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *217
उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2022

4जी नेटवर्क से वंचित जिले

*217. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के कई जिले अब भी 4जी नेटवर्क से वंचित हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 4जी नेटवर्क से वंचित जिलों की संख्या कितनी है; और
- (घ) उक्त वंचित जिलों और गांवों तक 4जी सेवाएं कब तक पूरी तरह से पहुंच जाएंगी?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जारी.....2/

"4जी नेटवर्क से वंचित जिले" के संबंध में दिनांक 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *217 के भाग (क) से (घ) के संबंध में लोकसभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाई और राज्य सरकार से मार्च 2022 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 6,44,131 गांवों में से (गांवों की संख्या नवंबर 2019 तक भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार है) लगभग 5,98,951 (93%) गांवों में 4जी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है और 45,180 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1,05,531 गांवों में से लगभग 1,05,146 (99%) गांवों में 4जी मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(घ) सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) देश में चरणबद्ध तरीके से दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाते हैं। सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्तपोषण करके देश के मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित सभी गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए मुख्य यूएसओएफ स्कीमों निम्नानुसार हैं:

- देश में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सचुरेशन। परियोजना की अनुमानित लागत 26,316 करोड़ रुपये है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चरण-II में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करना। परियोजना की अनुमानित लागत 2211 करोड़ रुपये है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चरण-I के सभी स्थलों को 2जी से 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी में उन्नयन करना। परियोजना की अनुमानित लागत 2425 करोड़ रुपये है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करना। स्कीमों की अनुमानित लागत रु. 3637 करोड़ रुपये है।
- आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना और चार राज्यों (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7152 करोड़ रुपये है।
- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमा क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सेवा से वंचित 354 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना। परियोजना की अनुमानित लागत 337 करोड़ रुपये है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दूरसंचार सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और एनएच 223 पर निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान करना। परियोजना की अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपये है।

अनुलग्नक-1

माननीय सांसदों द्वारा "4जी नेटवर्क से वंचित जिले" के संबंध में दिनांक 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *217 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक देश के गांवों में 4जी कवरेज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार स्थिति (मार्च 2022 तक) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरजीआई डेटा के अनुसार गांवों की कुल संख्या (दिनांक 30-11-2019)	4जी से कवर किए गए गांवों की संख्या	4जी कवरेज से वंचित गांवों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	559	105	454
2	आंध्र प्रदेश	17328	14159	3169
3	अरुणाचल प्रदेश	5993	2262	3731
4	असम	26429	24223	2206
5	बिहार	44888	44575	313
6	छत्तीसगढ़	20072	17482	2590
7	चंडीगढ़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	95	62	33
9	गोवा	392	342	50
10	गुजरात	18425	17604	821
11	हरियाणा	6640	6629	11
12	हिमाचल प्रदेश	20852	18970	1882
13	जम्मू और कश्मीर	6474	5643	831
14	झारखंड	32370	30050	2320
15	कर्नाटक	29818	28634	1184
16	केरल	1438	1358	80
17	लद्दाख	243	92	151
18	लक्षद्वीप	27	10	17
19	मध्य प्रदेश	55058	51818	3240
20	महाराष्ट्र	43931	40138	3793
21	मणिपुर	2612	2069	543
22	मेघालय	7100	4580	2520
23	मिजोरम	867	618	249
24	नागालैंड	1535	1073	462

25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	55	55	0
26	ओडिशा	51176	43584	7592
27	पुदुचेरी	96	95	1
28	पंजाब	12534	12519	15
29	राजस्थान	46077	42343	3734
30	सिक्किम	461	157	304
31	तमिलनाडु	16488	15916	572
32	तेलंगाना	10203	9951	252
33	त्रिपुरा	937	638	299
34	उत्तर प्रदेश	105531	105146	385
35	उत्तराखंड	16456	15215	1241
36	पश्चिम बंगाल	40971	40836	135
कुल		644131	598951	45180
